Finance Commission are deliberated by an informal Study Group which includes representatives of some State Governments while prescribing the terms of reference.

(c) It was not considered necessary to consult the State Governments on the composition of Finance Commission nor to remit this matter to the Inter-State Council.

Streamlining the Taxation System

74. SHRI IQBAL SINGH : Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration for streamlining and simplifying the various procedures in the taxation system to create an atmosphere of mutual trust and confidence between assessees and assessing authorities;

(b) if so, the details thereof and if not. the reasons therefor; and

(c) what steps are being taken by Government to simplify the taxation system?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.V. CHANDRASHEKHAR MURTHY):(a) to (c) Simplification of tax laws is an ongoing process. While in view of the proximity to the presentation of the Budget it is not possible to specify the proposals under consideration. It may broadly be mentioned that, as a part of the on-going Budget exercise, a number of recommendations made by the Chelliah Committee as well as suggestions received from the public arc under consideration. The Government's decisions, if any, would be reflected in the Finance Bill, 1994.

कार / स्कूटर अग्रिम में वृद्धि

75. **मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मोटरकार, स्कूटर आदि को खरीदने के लिए दिए जाने वाले अग्रिम की अधिकतम सीमा में वृद्धि किए जाने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुए है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो इस का पूर्ण ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) और (ख) वाहन की वास्तविक लागत को पूरा करने के लिए मोटरकार, स्कूटर आदि को खरीदने हेतु अग्रिम की अधिकतम सीमा में वृद्धि करने के संबंध में समय-समय पर अनुरोध प्राप्त होते रहे हैं। संसाधनों की कमी को ध्यान में रखते हुए मोटरकार / स्कूटर अग्रिमों की राशि में वृद्धि करना संभव नहीं हो पाया है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

राज्यों द्वारा अधिविकर्ष (ओवरड्राफ्ट) लिया जाना

76. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 दिसम्बर, 1993 तक विभिन्न राज्यों, विशेष रूप से राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्यों द्वारा लिए गए अधिविकर्ष का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार इन अधिविकर्षों को पूरा करने के लिए विशेष अनुदान जारी करने का विचार रखती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) वित्तीय वर्ष 1993-94 (1 अप्रैल से 31 दिसम्बर, 1993) के दौरान निम्नलिखित राज्य सरकारों को रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट लेने पड़े:—

राज्य	ओवरड्राफ्ट की अधिकतम राशि
1. असम	137.92
2. बिहार	203.79